

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :- संजू शर्मा, आर० ए० एस०)

अपील संख्या :- 28/2008 (वित्तिघ)

उनवान :- 1. लालाराम पुत्र मदन कन्हैया जाति अहीर निवासी ग्राम भोजराजका तहसील कोटकासिम जिला अलवर ।

:- अपीलांट

बनाम

1. महावीर,
2. मनपाल,
3. राजेन्द्र उर्फ राजाराम,
4. धासीराम पुत्रान झूथर जाति अहीर निवासी ग्राम भोजराजका तहसील कोटकासिम जिला अलवर

:- रेषपो

अपील विरुद्ध निर्णय उपखंड अधिकारी, कोटकासिम
दिनांक 12.6.2008

उपस्थित :- 1. वकील अपीलांट :- श्री जनार्दन शर्मा
2. वकील रेषपो :- सर्व श्री भगवानसहाय शर्मा
जगदीश प्रसाद शर्मा,
हरिप्रसाद शर्मा

निर्णय

दिनांक 22.8.2016

1. प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखंड अधिकारी, कोटकासिम द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 24/2006 उनवान महावीर बनाम लालाराम वगैरा में पारित आदेश दिनांक 12.6.08 के विरुद्ध है, जिस निर्णय के द्वारा प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया गया है ।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी महावीर ने उपखंड अधिकारी, कोटकासिम के यहां एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल० आर० एक्ट इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 448 रकबा 14 बिस्वा बाके ग्राम भोजराजका

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अधिकारी अलवर

तहसील कोटकासिम प्रार्थी एवं तरतीबी अप्रार्थी की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है । अप्रार्थी असल की आराजी इस आराजी से लगती हुई है । प्रार्थी एवं तरतीबी अप्रार्थी की कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि की डोल को लेकर असल अप्रार्थी आये दिन झगडा करते हैं । प्रार्थी एवं तरतीबी अप्रार्थी ने तहसीलदार कोटकासिम के आदेश क्रमांक 67 दिनांक 5.6.2005 को अपनी आराजी की पैमायश कराई हुई है । अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पैमायश रिपोर्ट दिनांक 5.6.2005 के अनुसार पत्थरगट्टी कराने का आदेश फरमावे । विद्वान उपखंड अधिकारी कोटकासिम द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया है, जिसके विरुद्ध यह अपील अप्रार्थी ने पेश की है ।

3. विद्वान वकील अप्रार्थी अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि विद्वान तहत न्यायालय का निर्णय जिस पैमायश रिपोर्ट दिनांक 5.6.2005 के आधार पर पारित किया गया है, वह पैमायश रिपोर्ट विधिसम्मत नहीं है । पैमायश रिपोर्ट तैयार करते समय मुझे नहीं बुलाया गया । इकतरफा में रिपोर्ट तैयार की गई है । कानूनन सभी पक्षकारान की उपस्थिति में एव मुस्तकिल पॉइंट से पैमायश कर रिपोर्ट तैयार कराई जानी चाहिये । तहत न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत नहीं है । अतः अपील स्वीकार की जावे ।

4. जवाब में विद्वान वकील प्रार्थी रेस्पोंडेंट का कथन है कि विवादित भूमि हमारी कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि है, जिसकी डोल को लेकर अप्रार्थी असल आये दिन झगडा करते हैं । पैमायश रिपोर्ट विधिसम्मत तैयार की गई है । तहत न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत है । अतः अपील खारिज की जावे ।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । प्रकरण के गुणावगुण पर विचार करने से पूर्व हमारे समक्ष निम्न विवाधक उभर कर सामने आये हैं :-

1. क्या धारा 128 एल0 आर0 एक्ट के प्रार्थना पत्र पर आदेश पारित करने वाले अधिकारी की हैसियत उपखंड अधिकारी की है अथवा भू अभिलेख अधिकारी की है ।

2. अगर धारा 128 के प्रार्थना पत्र पर उपखंड अधिकारी भू अभिलेख अधिकारी की हैसियत से आदेश पारित करता है तो क्या उसकी अपील राजस्व अपील अधिकारी को लाई करेगी अथवा नहीं ।

विवाधक बिन्दू :- 1

क्या धारा 128 एल0 आर0 एक्ट के प्रार्थना पत्र पर आदेश पारित करने वाले अधिकारी की हैसियत उपखंड अधिकारी की है अथवा भू अभिलेख अधिकारी की है ।

इस सम्बन्ध में हमने धारा 75 एवं 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम में दिये गये प्रावधानों का अध्ययन किया । धारा 75 में प्रावधान दिया गया है कि भू राजस्व अधिनियम के तहत पारित आदेशों की प्रथम अपील धारा 75 के तहत होगी ।

धारा 128 एल0 आर0 एक्ट में प्रावधान दिया गया है कि इस धारा के तहत पेश प्रार्थना पत्र पर उपखंड अधिकारी भू अभिलेख अधिकारी की हैसियत से आदेश पारित करता है. इसलिये इसके विरुद्ध अपील भू अभिलेख निदेशक को होगी। इस प्रावधान की 1993 आर0 आर0 डी0 720 में व्याख्या की गई है, जिसका भी हमने अध्ययन किया। इस न्यायिक दृष्टांत के तथ्य इस प्रकार हैं कि उपखंड अधिकारी बीकानेर (उत्तर) ने धारा 128 एल0 आर0 एक्ट के प्रार्थना पत्र पर आदेश पारित किया। इसकी अपील राजस्व अपील अधिकारी को हुई। राजस्व अपील अधिकारी ने ज्यूरिसडिक्शन (अधिकारिता) के बिन्दू पर अपील खारिज की। प्रकरण आगे माननीय राजस्व मण्डल में पेश हुआ। माननीय राजस्व मण्डल ने अभिनिर्धारित किया कि धारा 128 पर उपखंड अधिकारी भू अभिलेख अधिकारी की हैसियत से ही आदेश पारित करता है। आदेश पर अगर उपखंड अधिकारी की सील लगा दी जाती है तो भी वह आदेश भू अभिलेख अधिकारी द्वारा ही पारित किया हुआ माना जावेगा। इसके विरुद्ध अपील भू अभिलेख निदेशक को होगी, राजस्व अपील अधिकारी ने अधिकारिता के बिन्दू पर सही तौर पर अपील खारिज की है।

इसके अलावा न्यायिक दृष्टांत 2002 आर0 आर0 डी0 326 तथा 2002 (2) आर0 आर0 टी0 पेज 863 में प्रतिपादित सिद्धान्तों का भी अध्ययन किया। इन न्यायिक दृष्टांतों के सारगर्भित तथ्य इस प्रकार हैं कि उपखंड अधिकारी ने भू अभिलेख अधिकारी की हैसियत से आदेश पारित किया। इसकी अपील राजस्व अपील अधिकारी को हुई। राजस्व अपील अधिकारी ने अधिकारिता के बिन्दू पर अपील खारिज की। प्रकरण आगे माननीय राजस्व मण्डल में इस आधार पर पेश किया गया कि राजस्व अपील अधिकारी को अपील खारिज न करके सक्षम न्यायालय में पेश करने हेतु लौटाना चाहिये था। माननीय राजस्व मण्डल ने अभिनिर्धारित किया कि रेवेन्यू कोर्ट्स मैन्चूअल में अपील को लौटाने का कोई प्रावधान नहीं है, राजस्व अपील अधिकारी ने सही तौर पर अपील खारिज की है।

2. विवाधक नम्बर 02 :-

अगर धारा 128 एल0 आर0 एक्ट के प्रार्थना पत्र उपखंड अधिकारी भू

अभिलेख अधिकारी की हैसियत से आदेश पारित करता है तो क्या इसकी अपील राजस्व

अपील अधिकारी को लाई करेगी अथवा नहीं

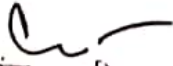
धारा 75 (च) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम में प्रावधान दिये हुये हैं कि भू अभिलेख अधिकारी द्वारा दिये गये आदेश के विरुद्ध भू अभिलेख निदेशक को धारा 75 एल0 आर0 एक्ट के तहत अपील की जा सकती है।

Land Revenue Law in Rajasthan Writer S. K. Dutt Revised and Enlarged Edition 2007 में धारा 75 पेज नम्बर 203 के बिन्दू नम्बर 09 में राजस्व अपील अधिकारी की अधिकारिता के बारे में बताया गया है कि R.A.A. has no jurisdiction to hear appeal U/S 75 against of S.D.O. passed in capacity of Land Record Officer, order passed by R.A.A. rejecting appeal is justified.

6. उपरोक्त समस्त तथ्यों के विवेचन की रोशनी में एवं धारा 75 व 128 एल0 आर0 एक्ट तथा उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट हो जाता है कि धारा 128 एल0 आर0 एक्ट के प्रार्थना पत्र पर उपखंड अधिकारी भू अभिलेख अधिकारी की हैसियत से आदेश पारित करता है, चाहे उस आदेश पर उपखंड अधिकारी की रील ही क्यों ना लगी हो और उस आदेश की अपील धारा 75 एल0 आर0 एक्ट के तहत राजस्व अपील अधिकारी के श्रवणाधिकार में नहीं है । चूंकि प्रस्तुत अपील उपखंड अधिकारी द्वारा भू अभिलेख अधिकारी की हैसियत से धारा 128 एल0 आर0 एक्ट के प्रार्थना पत्र पर पारित आदेश के विरुद्ध पेश की गई है, जो कि उपरोक्त समस्त प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में राजस्व अपील अधिकारी के श्रवणाधिकार में नहीं है । लिहाजा अपील अपीलांट ज्यूरिसडिक्शन (अधिकारिता) में नहीं होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है ।

7. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट अधिकारिता में नहीं होने के कारण खारिज की जाती है ।

8. निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । तहत पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ वापिस लौटाई जावे । पत्रावली फ़ैसल शुमार हो ।


(संजू शर्मा)

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर